

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग

विषय:— जनपद—देहरादून के अन्तर्गत महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर, देहरादून में इण्डोर कीड़ा हॉल के नवीनीकरण के निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—1242/38वें राजपत्रा/2016-17/देहरादून, दिनांक 16 फरवरी, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद—देहरादून के अन्तर्गत महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर, देहरादून में इण्डोर कीड़ा हॉल के नवीनीकरण के निर्माण कार्य हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए प्रस्तुत आगणन ₹ 225.38 लाख के सापेक्ष टी०ए०सी० के परीक्षणोपरान्त संस्तुत आंकित धनराशि ₹ 205.46 लाख (सिविल निर्माण कार्यों हेतु ₹ 35.40 लाख तथा अधिग्राहि नियमावली के अनुसार कराये जाने वाले कार्यों हेतु ₹ 170.06 लाख) की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रथम किश्त के रूप में ₹ 82.00 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या—730/VI/2016-21(17)/2016, दिनांक 20 अक्टूबर, 2016 के उपरान्त अवशेष बची धनराशि ₹ 123.46 लाख के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में द्वितीय चरण के निर्माण कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में 40% यानीकि ₹49.00 लाख (₹ उनचास लाख मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

2. उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं०-318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014, में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। उक्त कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्त विभाग के शासनादेश सं०-474/XXVII(7)/2008 दि०-15-12-08 के विहित शर्तों के अनुसार कार्यदायी संस्था से निर्धारित प्रपत्र पर एम०ओ०य०० अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि मदवार स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

4. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोनिंगिं द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

5. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली-भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

6. अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण शासन को प्रेषित किये जाय तथा समस्त कार्य निर्धारित समय अवधि के भीतर ही पूर्ण किया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।

7. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या—2047/XIV—219(2006), दिनांक 30—5—2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

8. अधिप्राप्ति कार्यों हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

9. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका से करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। कार्य करते समय टेंडर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेंडर करने में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जाय।

10. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। तथा विलम्ब के कारण आगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा। कार्य का गुणवत्ता परीक्षण नियोजन विभाग द्वारा चयनित संस्था से कराये जाने हेतु प्रस्ताव समयान्तर्गत नियोजन विभाग को प्रेषित करते हुए समयबद्ध कार्यवाही की जायेगी।

11. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2016—17 में अनुदान संख्या—11—आयोजनागत—लेखाशीर्षक—4202—शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत व्यय—03 खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम—102—खेलकूद स्टेडियम—26—38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन—35—पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान पक्ष के नामे डाला जायेगा।

12. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या—847/XXVII(1)/2016, दिनांक 26 जुलाई, 2016 में दिये गये निर्देशों के कम में निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक :— अलाटमैट आईडी० संख्या—९१७०३।।००।। दिनांक २ फ़रवरी, २०१७

भवदीय,

(शैलेश बगौली)

प्रभारी सचिव।

पृष्ठांकन संख्या— 109 /VI/2017–21(17)/2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओबराय बिल्डिंग, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा० खेल मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—३, उत्तराखण्ड शासन।
7. जिला कीड़ाधिकारी, देहरादून।
8. महाप्रबन्धक / परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम (खेल इकाई), देहरादून।
9. एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।